REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

''छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अंत्योदय अन्न योजना का मूल्यांकन''

ज्ञानेश कुमार[1] डॉ. श्रीमति संजू पाण्डेय[2]
[1] शोध छात्र अर्थशास्त्र विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
[2]सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, शास. निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा बिलासपुर (छ.ग.)

शोध सार :–

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। यह परिवारों को सामाजिक सुरक्षा जाल एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। चयनित वस्तुएं सहायिकी मूल्य पर पात्र हितग्राहियों को प्रदान की जाती है। गरीबी व बेरोजगारी आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण लोग भूखमरी एवं कुपोषण के षिकार हो जाते हैं। जब तक मानव भोजन से संतुष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति विकास के संबंध में नहीं सोच सकता अर्थात् व्यक्ति के मानवीय जीवन की समस्त क्रियाएं दिषाहीन हो जाती है और वह अनैतिक एवं असामाजिक घटनाओं को अंजाम देना आरंभ कर देता है। अतः मानवीय जीवन के पोषण के लिए खाद्यान्न ही अति आवष्यक तत्त्व है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर स्पष्ट किया गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था में कुल भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 64.20 करोड़ से अधिक है।[1]

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में किये प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है। यह योजना पात्र हितग्राहियों जीवनयापन के लिए सार्थक सहयोग प्रदान करता है। कुल 80 हितग्राहियों में से अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिशत 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजातियों का कुल 32.5 प्रतिशत है। ये लोग आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए है। इस समुदाय के अधिकतर लोग कृषि कार्य एवं दैनिक मजदूरी पर निर्भर है।

मुख्य शब्द :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा और भूखग्रस्त।

प्रस्तावना :–

आज विश्व में सबसे ज्यादा गरीब एवं कुपोषित लोग भारत में रहते हैं।[2] विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान, भारत दूसरे स्थान तथा अमेरिका तीसरे स्थान पर है तथा विश्व की 19.4% जनसंख्या चीन में, 17.5% जनसंख्या भारत में एवं 4.5% जनसंख्या अमेरिका में निवास करती है। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011–12 में भारत की कुल जनसंख्या का 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही

1. विष्व खाद्य संगठन रिपोर्ट, 16 अक्टूबर 2009
4. Ashok Gulati & Shweta Saini (2014) "The National Food Security Act; challenges and options",IndianEconomy since Independence, Uma Kapila, Chapter 13, Page No. 317

थी।[3] विष्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में विश्व के 33% गरीब भारत में थे जो 30 वर्ष पहले 1981 में 22% थी।[4] विश्व के तीन कुपोषित बच्चों में 1 कुपोषित बच्चा भारत का है।[5] तेन्दुलकर कमेटी 2011–12 के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में 44.6% (88.9 लाख) लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे तथा शहरी क्षेत्र में 24.8% (15.2 लाख) लोग गरीबी रेखा से नीचे थे तथा पूरे छत्तीसगढ़ में 39.9% (104.1 लाख) लोग गरीब थे।[6]

शोध समस्या का चयन :–

छत्तीसगढ़ 2000 में नवगठित राज्य है। यह एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। यहां की 77% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण एवं लक्ष्यांकित चुनौती भूखमरी, गरीबी एवं बेरोजगारी है जो कि मानवीय विकास में बहुत बड़ी बाधा है। अंत्योदय अन्न योजना के लागू होने के लगभग 14 वर्षों के बाद भी यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी गरीबों को दो समय का भोजन मिल रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

- शोध क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन का योजना के हितग्राहियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शून्य परिकल्पना :–

- अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के उन्नयन में प्रभावपूर्ण भूमिका नहीं रही।

अध्ययन की सीमाएं :–

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य में अंत्योदय अन्न योजना का मूल्यांकन करने हेतु रायगढ़ जिले का अध्ययन किया गया है।

शोध प्राविधि :–

प्रस्तुत अध्ययन ''छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अंत्योदय अन्न योजना का मूल्यांकन'' का अध्ययन करने हेतु सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन सविचार निदर्शन विधि से किया गया है। इसी प्रकार अध्ययन का T-Test से परीक्षण किया गया है।

---

3. Report of the expert group to review the Methodology for Measurement of Poverty, Government of India, Planning Commission, June 2014
4. World Bank (2013), State of the Poor, Where are the poor and where are they poorist? Draft by Olinto and Uematry H. Poverty reduction of equity deportment of the World Bank.
5. Hungama (2011), Hungama Fighting Hunger and Malnutrition, The Hungama Report 2011
6. Report of the expert group to review the Methodology for Measurement of Poverty, Government of India, Planning Commission, June 2014

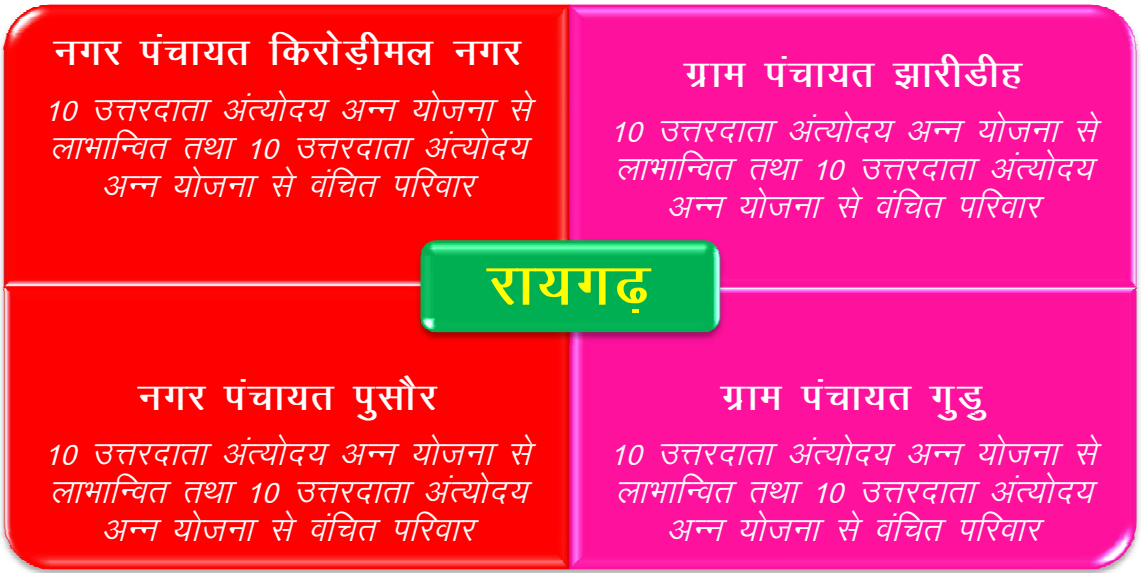

हितग्राहियों का लिंगानुपात एवं उनका प्रतिशत :–

सर्वेक्षित क्षेत्र में कुल 80 हितग्राहियों में से 75 (93.75%) महिलाएं पायी गई तथा 5 (6.25%) पुरूष हितग्राही पाये गये।

लिंग	संख्या	प्रतिशत
पुरूष	5	6.25
महिला	75	93.75
कुल	80	100

स्त्रोतः– प्राथमिक सर्वे (दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक)

हितग्राहियों का आयुवर्ग एवं उनका प्रतिशत :–

रायगढ़ के कुल 80 हितग्राहियों में से सबसे अधिक 27 (33.75%) हितग्राही 31–40 आयुवर्ग के पाये गये तथा सबसे कम 8 (10%) हितग्राही 20–30 आयुवर्ग के पाये गये। 50 से अधिक आयुवर्ग के कुल 22 (27.5%) हितग्राही पाये गये।

आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
20–30	8	10
31–40	27	33.75
41–50	23	28.75
50 से अधिक	22	27.5
कुल	80	100

स्त्रोतः– प्राथमिक सर्वे (दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक)

हितग्राहियों का शिक्षा स्तर एवं उनका प्रतिशत :–

हितग्राहियों के शैक्षणिक स्तर को प्रदर्षित किया गया है। षिक्षा के स्तर को कुल 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुल 80 हितग्राहियों में से 48 (60%) अषिक्षित हितग्राही पाये गये जबकि 18 (22.5%) हितग्राही प्राथमिक स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर पर 13 (16.25%) हितग्राही पाये गये जबकि सेकण्डरी स्तर केवल 1 (1.25%) हितग्राही पाया गया।

शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	48	60
प्राथमिक	18	22.5
माध्यमिक	13	16.25
सेकेण्डरी	1	1.25
उच्च शिक्षा	0	0
कुल	80	100

स्त्रोतः– प्राथमिक सर्वे (दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक)

हितग्राहियों का समुदाय, संख्या एवं उनका प्रतिशत :–

कुल 80 हितग्राहियों में से 28 (35%) हितग्राही अनुसूचित जाति के तथा 26 (32.5%) हितग्राही अनुसूचित जनजाति के पाये गये जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 (31.25%) व केवल 1 (1.25%) हितग्राही सामान्य जाति का पाया गया।

समुदाय	संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	28	35
अनुसूचित जनजाति	26	32.5
अन्य पिछड़ा वर्ग	25	31.25
सामान्य	1	1.25
कुल	80	100

स्त्रोतः– प्राथमिक सर्वे (दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक)

वर्ष 2000 से पूर्व बीपीएल परिवारों द्वारा खाद्यान्न क्रय करने का मासिक औसत व्यय (में) तथा वर्तमान में अंत्योदय परिवारों द्वारा क्रय किये गये खाद्यान्नों पर मासिक औसत व्यय (में) की तुलनात्मक विवरण :–

वर्ष 2000 से पूर्व बीपीएल योजना के अंतर्गत चांवल पर मासिक औसत व्यय ` 46.29 तथा वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चांवल पर मासिक औसत व्यय ` 35 हो रहा है। वर्ष 2000 से पूर्व गेहू पर मासिक औसत व्यय ` 8.9 होता था जबकि वर्तमान में सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षित क्षेत्र में गेहू का वितरण नहीं हो रहा था। इसी प्रकार वर्ष 2000 से पूर्व चीनी पर मासिक औसत व्यय ` 10.12 होता था जबकि वर्तमान में चीनी पर मासिक औसत व्यय ` 13.5 हो रहा था। वर्ष 2000 से पूर्व मिट्टी तेल पर मासिक औसत व्यय ` 6.8 होता था जबकि वर्तमान में मिट्टी तेल पर मासिक औसत व्यय ` 29.54 हो रहा था।

वर्ष 2000 के पूर्व हितग्राहियों का बीपीएल योजना के अंतर्गत कुल खाद्यान्न पर मासिक औसत व्यय ` 72.12 हो रहा था जबकि वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत मासिक औसत व्यय ` 78.04 हो रहा था।

क्र.	खाद्यान्न	वर्ष 2000 से पूर्व बी.पी.एल. योजनांतर्गत	वर्तमान में अंत्योदय (2016) योजनांतर्गत
1.	चांवल	46.29	35
2.	गेंहू	8.9	0
3.	चीनी	10.12	13.5
4.	मिट्टी तेल	6.8	29.54
5.	काला चना	0	0
6.	दाल	0	0

7.	नमक	0	0
8.	अन्य	0	0
	कुल	72.12	78.04

स्त्रोतः— प्राथमिक सर्वे (दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक)

उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल मासिक औसत व्यय में अंतर खाद्यान्न में मात्रात्मक वृद्धि के कारण हुआ है।

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Rice	46.2875	80	19.08090	2.13331
	Post_Rice	35.0000	80	.00000	.00000
Pair 2	Pre_Sugar	10.1250	80	6.79049	.75920
	Post_Sugar	13.5000	80	.00000	.00000
Pair 3	Pre_Kirosin	6.8047	80	4.25711	.47596
	Post_Kirosin	30.1750	80	6.32911	.70762

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pre_Rice & Post_Rice	80	.	.
Pair 2	Pre_Sugar & Post_Sugar	80	.	.
Pair 3	Pre_Kirosin & Post_Kirosin	80	.680	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pre_Rice - Post_Rice	11.28750	19.08090	2.13331	7.04125	15.53375	5.291	79	.000
Pair 2	Pre_Sugar - Post_Sugar	3.37500	6.79049	.75920	4.88615	1.86385	4.445	79	.000
Pair 3	Pre_Kirosin - Post_Kirosin	23.37031	4.64233	.51903	24.40341	22.33721	45.027	79	.000

Ho- अंत्योदय अन्न योजना रायगढ़ जिले के हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के उन्नयन में प्रभावपूर्ण भूमिका नहीं रही।

परिणामः— Table value of t at 5% and 79df (2 tail) = 1.99
Table value of t at 1% and 79df (2 tail) = 2.88

t- Calculated Value> t-Table Value
*5.291 > 1.99 *4.445 > 1.99 **45.027 > 1.99
* सार्थक ** उच्च सार्थक

अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है अर्थात् निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि अंत्योदय अन्न योजना से आर्थिक सुधार हुआ है।

निष्कर्ष :–

- कुल 93.75 प्रतिशत हितग्राही महिलायें पायी गईं।
- कुल 80 हितग्राहियों में से सबसे अधिक 27 (33.75%) हितग्राही 31–40 आयुवर्ग के पाये गये।
- कुल 48 (60%) अशिक्षित हितग्राही पाये गये।
- कुल 28 (35%) हितग्राही अनुसूचित जाति के तथा 26 (32.5%) हितग्राही अनुसूचित जनजाति के पाये गये।
- वर्ष 2000 के पूर्व हितग्राहियों का बीपीएल योजना के अंतर्गत कुल खाद्यान्न पर मासिक औसत व्यय ` 72.12 हो रहा था जबकि वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत मासिक औसत व्यय ` 78.04 हो रहा था। हितग्राहियों के कुल मासिक औसत व्यय में अंतर खाद्यान्न में मात्रात्मक वृद्धि के कारण हुआ है क्योंकि वर्ष 2000 से पूर्व खाद्यान्न की मात्रा में बहुत कम थी जबकि वर्तमान में अन्त्योदय अन्न योजना के द्वारा हितग्राहियों को 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुझाव :–

- सर्वेक्षण के दौरान अवलोकित किया गया कि उचित मूल्य की दुकान महीने में केवल एक सप्ताह ही खुलता है जिससे हितग्राहियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः उचित मूल्य की दुकान को प्रतिदिन शाम के समय खोलना चाहिए जिससे हितग्राहियों की एक दिन की मजदूरी बच जाए।
- सर्वेक्षण के दौरान अवलोकित किया गया कि गेहूं, दाल व नमक का वितरण नहीं हो रहा है। अतः गेहूं, दाल व नमक का वितरण पुनः शुरू होना चाहिए।
- सर्वेक्षण के दौरान ज्यादातर हितग्राही ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि उन्हें प्रोटिनयुक्त आहार, सब्जी व खाद्य तेल के लिए आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए जिससे हितग्राहियों के भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व शामिल हो सके।
- हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न उनके समय, उपलब्धता और मुद्रा के अनुसार लेने की छुट मिलनी चाहिए जिससे हितग्राहियों को विपरित परिस्थितियों में भी खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।
- उपभोक्ता समितियों का गठन और सशक्तिकरण की भी आवष्यकता है जो समय–समय पर भण्डारण का सत्यापन कर सके।
- प्रतिदिन की उपलब्ध खाद्यान्न भण्डार की जानकारी तथा खाद्यान्न वितरित किये जाने वाले दिनों की निश्चित घोषणा की जानी चाहिए जिससे हितग्राहियों को खाद्यान्न की उपलब्धता की जानकारी तथा उसे क्रय करने की सुविधा मिल सके।

संदर्भ ग्रंथसूची :–

1. विश्व खाद्य संगठन रिपोर्ट, 16 अक्टूबर 2009
2. Ashok Gulati & Shweta Saini (2014) "The National Food Security Act; challenges and options", Indian Economy since Independence, Uma Kapila, Chapter 13, Page No. 317
3. Report of the expert group to review the Methodology for Measurement of Poverty, Government of India, Planning Commission, June 2014

4. World Bank (2013), State of the Poor, Where are the poor and where are they poorist? Draft by Olinto and Uematry H. Poverty reduction of equity deportment of the World Bank.
5. Hungama (2011), Hungama Fighting Hunger and Malnutrition, The Hungama Report 2011
6. Report of the expert group to review the Methodology for Measurement of Poverty, Government of India, Planning Commission, June 2014
7. प्राथमिक सर्वे (दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक)
8. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (2014) "टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन्स सिस्टम, बेस्ट प्रैक्टिस सॉल्यूशन"
9. मुखर्जी, अमितावा (2012) फूड सिक्युरिटी इन एशिया, सेज.
10. पटनायक, उषा (2011) इम्पीरियलिज़्म, रिसोर्सेज एण्ड फूड सिक्युरिटी विथ रिफरेंस टू द इंडियन एक्सपीरियंस. इडी. वकार अहमद; अमिताभ कुन्दु; रिचर्ड पीट. इंडियाज़ न्यू इकॉनामिक पॉलिसी – ए क्रिटिकल एनालिसिस. रावत पब्लिकेशन जयपुर एण्ड दिल्ली
11. घोष, अर्पिता (2011) ग्लोबलाईजेशन, एग्रिकल्चर ग्रोथ एण्ड फूड सिक्युरिटी इन इंडिया. दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन प्रा.लि., नई दिल्ली.